30 नवंबर 2020

प्रेस विज्ञप्ति

नेटवर्क ऑफ रूरल एंड एग्रेरियन स्टडीज (NRAS) द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन वेबिनार में आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉ वी रामगोपाल राव द्वारा "**स्टेट ऑफ रूरल एंड एग्रेरियन इंडिया रिपोर्ट 2020**" ("**भारत में खेती और गाँव-देहात का हाल 2020**) का विमोचन किया गया। यह रिपोर्ट NRAS द्वारा तैयार की गयी है, जो वर्ष 2010 में स्थापित किया गया ग्रामीण और कृषि भारत के मुद्दों से जुड़े अध्येताओं, शोधकर्ताओं, किसानों, छात्रों और कार्यकर्ताओं का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली कई वर्षों से NRAS के काम को समर्थन देता आया है, विशेष रूप से 2019 के NRAS के दूसरे नीति सम्मेलन के आयोजन में, जो आज जारी की गयी रिपोर्ट का आधार बना।

यह रिपोर्ट समकालीन ग्रामीण भारत के हालात का व्यापक और आलोचनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करने की एक कोशिश है। इसमें ग्रामीण भारत की आर्थिक और पारिस्थितिक दशा के पीछे मौजूद प्रमुख ढांचागत आयामों, विशेषकर नीतियों और रुझानों पर ख़ास ध्यान दिया गया है। इस रिपोर्ट को जारी करते हुए, डॉ राव ने कहा कि यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण और स्पष्ट रूप से लिखी गयी है और इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए ताकि गाँव-देहात और खेती से जुड़े सभी लोगों और संस्थानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संसाधन बने। उन्होंने गाँव की समस्याओं को सुलझाने में तकनीकी उपायों की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा किये जा रहे एक अनुसंधान का उदाहरण दिया जिसके तहत पड़ोसी राज्य पंजाब में पराली जलाए जाने की समस्या से निपटने के लिए पराली को पुनः उपयोग (रिसाइकल) करने के तरीके विकसित किये जा रहे हैं। NRAS की संस्थापक सदस्या डॉ ए आर वासवी ने गलत नीतियों और रूढ़िवादी विचारों के कारण ग्रामीण आजीविका पर लगातार हो रहे प्रहार, प्राकृतिक संसाधनों के विनाश और ग्रामीण नागरिकों की कंगाली की प्रक्रिया पर लगाम लगाने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट कृषि के मुख्यधारा के मॉडल में निहित समस्याओं पर प्रकाश डालती है और नए विकल्पों की दिशा की ओर इशारा करती है। श्री पी एस विजयशंकर (समाज प्रगति सहयोग, मध्य प्रदेश) ने रिपोर्ट के

प्रमुख संदेशों को दोहराते हुए, उत्पादकता और लोक-लुभावनी नीतियों पर आधारित दृष्टिकोणों से आगे जाकर, कृषि-पारिस्थितिकी (एग्रोइकोलॉजी) को केंद्र में रखने वाली नई ग्रामीण नीतियों की तरफ बढ़ने की अनिवार्यता को रेखांकित किया।

इसके बाद हुई पैनल चर्चा में, दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफ़ेसर सतीश देशपांडे ने कहा कि ग्रामीण की अवधारणा पर गहराई से उपनिर्विचार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण को आमतौर पर किसी अवशेष के रूप में देखा जाता है, जो या तो लुप्त हो जाने वाला है या किसी अंतिम स्वरुप की ओर अग्रसर समाज की बीच की कड़ी है। उन्होंने रिपोर्ट में ग्रामीण को एक उत्पादक, सकारात्मक जगह के रूप में देखने की अवधारणा का समर्थन किया। उन्होंने "किसान" को एक समरूप श्रेणी के रूप में देखे जाने पर भी सवाल खड़े किये। श्री सिराज हुसैन, ICRIER, ने कहा कि भारत जैसे देश में एक ही प्रकार का समाधान हर क्षेत्र की समस्या को हल करने में कारगर नहीं हो सकता है और हर स्थानीय क्षेत्र के ख़ास आयामों के बारीक अध्ययन के माध्यम से समाधान विकसित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि रिपोर्ट में सिद्धांतों के आगे जाकर ठोस व्यावहारिक प्रस्तावों को भी शामिल किया जा सकते है। डॉ सुधा नारायणन, IGIDR, ने प्रभावशाली ग्रामीण नीतियों और दृष्टिकोणों को कृषि बाजारों के ढांचे में होने वाले परिवर्तनों, विशेष रूप से हाल ही में पारित किये गए तीन नए कृषि बिलों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों की सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग एक असाध्य एजेंडा है। उन्होंने विकल्प के तौर पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लागू किये गए विकेंद्रीकृत खरीद के कई उदाहरणों की ओर इशारा किया। एमएसपी या खरीद से आगे बढ़ते हुए, आज के संदर्भ में किसानों को किस प्रकार के सरकारी समर्थन की ज़रुरत है, इसपर चर्चा की ज़रुरत है और विपणन की बात करते समय, हमें पशुधन उत्पादों के लिए बाजार को भी शामिल करना चाहिए। श्री श्रीनिवासन अय्यर, फोर्ड फाउंडेशन, ने वर्तमान दृष्टिकोणों द्वारा उपेक्षित तीन सामाजिक समूहों के बारे में बात की - वनवासी, घुमन्तु पशुपालक और कारीगर। नई ग्रामीण नीतियों में, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में बसने और जीविकोपार्जन करने वाले इन सामाजिक समूहों के मुद्दों को संबोधित करने के तरीकों को खोजना होगा। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में गैर-लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी) के लिए एमएसपी व्यवस्था सुनश्चित करने के महत्व पर विशेष ज़ोर दिया, जिसका संभावित रूप से आजीविका पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। थनल संस्था से जुड़ी एस. उषा ने कहा कि कृषि-पारिस्थितिकी (एग्रोइकोलॉजी) को केन्द्र में रखते हुए वैकल्पिक नीतियाँ बनानी होंगी और ख़ास तौर पर औरतों के नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों और उनके ज्ञान के उत्पादन की प्रणाली, ग्रामीण क्षेत्रों और किसान समुदायों की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं।

अंतिम सत्र की खुली चर्चा के दौरान बुलन्दशहर के विख्यात किसान श्री भारत भूषण त्यागीजी ने खेती के संबंध में हमारे दृष्टिकोण को प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की नीव पर खड़ा करने की ज़रुरत को रेखांकित किया। जब हमारी समझ बदलेगी तभी कार्य और नीतियाँ बदलेंगी। खेती में मेहनत और श्रम न सिर्फ मूल्य के सृजन का माध्यम है बल्कि श्रम अपने आप में मूल्यवान है। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए श्री सिराज हुसैन ने कहा कि किसान की आमदनी एक अहम मुद्दा है और इसे संबोधित किये बिना किसानों के साथ कोई भी चर्चा शुरू नहीं की जा सकती है। उषा जी ने इस बात का समर्थन किया। अंत में डॉ ऋचा कुमार, असोसीयट प्रफ़ेसर, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने रिपोर्ट के प्रमुख संदेश को दोहराया - खेती और किसानों के लिए नीतियां बनाने में **पारिस्थितिकी** और **समता** को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने सब वक्ताओं और कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सहभागियों का धन्यवाद करते हुए कहा की एनआरएएस इस रिपोर्ट का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में करना चाहता है। विशेष रूप से यह रिपोर्ट किसानों तक जानी चाहिए। उन्होंने इस मुहिम में सभी से मदद और सहयोग की अपील की।

रिपोर्ट इस लिंक पर उपलब्ध है:

http://www.ruralagrarianstudies.org/state-of-rural-and-agrarian-india-report-2020/

चर्चा की रिकॉर्डिंग इस लिंक पर उपलब्ध है:

https://youtu.be/wwcHmVW7WZ0